केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क-bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :48 अंक 03 बुधवार 22 जुलाई 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

धरने पर बैठे राहुल को उठाकर ले गई पुलिस: प्रियंका–अखिलेश भी हिरासत में, शिक्षा मंत्री प्रधान को हटाने की मांग

नई दिल्ली (आभा)। पीएम आवास के पास मंगलवार दोपहर साढ़े तीन बजे धरने पर बैठे कांग्रेसियों को पुलिस शाम साढ़े 6 बजे उठाकर ले गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत कई नेता को हिरासत में ले लिया है। सरकार ने 3 घंटे के धरने में राहुल से 2 बार बातचीत की, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी पहुंचे तो कांग्रेसियों ने घेरा बना लिया और राहुल तक पहुंचने नहीं दिया। कांग्रेसियों और पुलिस के बीच आधे घंटे तक धक्का–मुक्की होती रही। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आखिर में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी उन्हें उठाकर ले गए और बस में बैठाया। जिस वक्त राहुल गांधी को उठाया जा रहा था, उनके साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी थे। इस दौरान राहुल गांधी की नाक से खून बहता नजर आ रहा है। आरोप है कि हिरासत में लिए जाने के दौरान राहुल गांधी की नाक में चोट लगी है। वहीं, नेता प्रतिपक्ष के सीने पर भी चोट लगने की बात कही जा रही है।

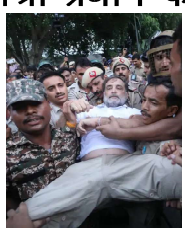

पीएम आवास के पास से हटाने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन पहुंचे थे। राहुल गांधी से करीब 20 मिनट बात की। इसके बाद जितेंद्र सिंह गृह मंत्री अमित शाह के पास गए। शाह से बातचीत के बाद उन्होंने फिर राहुल से बात की।

सोशल मीडिया पोस्ट में जितेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी की मांग थी कि नीट पर संसद में चर्चा हो। राहुल की यह मांग मान ली गई थी। लेकिन राहुल अपनी बात से मुकर गए। वह बोले– अब हमारी दो मांगे हैं। पहली– नीट पर संसद में चर्चा, दूसरी शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा।

संभल में घटकर 15: रह गए हिन्दू, योगी कैबिनेट में रिपोर्ट पेश

लखनऊ (आभा)। यूपी के संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के लिए गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग की रिपोर्ट मंगलवार को कैबिनेट में पेश की गई। न्यायिक आयोग की लगभग 450 पन्ने की रिपोर्ट विधानसभा के मानसून सत्र में विधानमंडल के पटल पर रखी जाएगी। न्यायिक आयोग ने पिछले वर्ष अगस्त में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी थी। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में हिंसा का कारण सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के भड़काऊ भाषण को ठहराया गया है,

कांवर यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन 5 दिनों तक बंद रहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–बस्ती । ,मण्डलायुक्त अखिलेश सिंह तथा आईजी संजीव त्यागी ने कावड़ यात्रा की तैयारी संबंधी अधिकारियों के साथ बैठक किया। बस में अधिकारियों के साथ आयुक्त कार्यालय से शास्त्री चौक, चेतक तिराहा, भूअर निरंजन, डारीडीहा होते हुए श्री भदेश्वर नाथ मंदिर तथा अयोध्या बॉर्डर तक बस में बैठकर अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी निर्धारित समय सीमा में कार्यों को पूरा करें, यह एक धार्मिक यात्रा है, उस में आने वाले कांवड़ियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास करें। उन्होंने कहा कि दुर्घटना मुक्त यात्रा पूरी करने का संकल्प लें तथा सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग सहित यात्रा पूरी कराएं।

आईजी संजीव त्यागी ने कहा कि प्रशासन द्वारा कांवड़ियों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा तथा पूर्व वर्षो की भांति सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

जिलाधिकारी श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना ने कहा कि यात्रा के दौरान कैमरे से पूरे यात्रा की निगरानी की जाएगी। उन्होंने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत तथा जिला पंचायत राज अधिकारी, ईओ नगर पालिका को निर्देशित किया है कि मुख्य पड़ाव स्थलों पर साफ–सफाई अभियान संचालित कराएं उन्होंने अमहट घाट पर मोटर बोट, नाव, तैराक, प्रकाश व्यवस्था की स्थापना कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने लोक निर्माण तथा एनएचआई विभाग को निर्देशित किया है कि मार्गो पर गड्ढों की भराई समय से करें।

पुलिस अधीक्षक डॉ यशवीर सिंह ने बताया कि कावड़ यात्रा के दौरान 7 अगस्त की शाम 4 बजे से से 11 जुलाई की रात तक राष्ट्रीय राज मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा।

निरीक्षण के दौरान सीडीओ सार्थक अग्रवाल, एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान, सीआरओ कीर्ति प्रकाश भारती सीएमओ डॉ. राजीव निगम उप जिलाधिकारी हिमांशु कुमार, उमाकान्त तिवारी, राजेश यादव, डीपीआरओ घनश्याम सागर, एएमए अशोक मद्धेशिया,अधिशासी अभियंता विद्युत , अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी अवधेश कुमार आदि शामिल रहे।

नेपाल से भटके बालक की घर वापसी, बस्ती सीडब्ल्यूसी ने नेपाल दूतावास के प्रतिनिधियों को सौंपा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बस्ती की बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने नेपाल से भटककर भारत आए एक बालक को उसके परिजनों तक पहुंचाने का रास्ता साफ कर दिया है। लंबी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया के बाद, सीडब्ल्यूसी ने मंगलवार दोपहर लगभग एक बजे नेपाल दूतावास के अधिकृत प्रतिनिधियों को बालक को उसके परिजनों को सौंपने का अधिकार पत्र सौंपा।

यह बालक नेपाल के कृष्णानगर का निवासी है और फरवरी माह में भटकते हुए बस्ती के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में मिला था। पुरानी बस्ती पुलिस ने उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। सीडब्ल्यूसी द्वारा कराई गई चिकित्सीय जांच और काउंसलिंग में बालक ने अपना पता नेपाल के कृष्णानगर का बताया। बालक के संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए, सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन प्रेरक मिश्रा और सदस्यों अजय श्रीवास्तव, डॉ. संतोष श्रीवास्तव तथा मंजू त्रिपाठी ने उसे वाराणसी के बाल गृह में आवासित कराने का आदेश दिया था। तब से बालक वहीं रह रहा था।

इस बीच, बस्ती सीडब्ल्यूसी ने नई दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास से लगातार संपर्क स्थापित किया और मामले की पूरी जानकारी साझा की। सीडब्ल्यूसी के प्रयासों के बाद, नेपाल दूतावास ने अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को बस्ती भेजा। इन प्रतिनिधियों ने बालक को बाल गृह से मुक्त कर नेपाल ले जाने का अनुरोध करते हुए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए।

सभी दस्तावेजों का गहन सत्यापन करने के बाद, सीडब्ल्यूसी ने बालक को नेपाल स्थित उसके घर पहुंचाकर परिजनों को सौंपने का आदेश जारी किया। इसके साथ ही, अधिकृत प्रतिनिधियों को अधिकार पत्र भी सौंप दिया गया।

सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन प्रेरक मिश्रा ने बताया कि दूसरे देश के बालक के मामले में सुपुर्दगी की प्रक्रिया सामान्य मामलों की तुलना में अधिक संवेदनशील और जटिल होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही बालक को नेपाल भेजने की अनुमति दी गई है, ताकि उसकी सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित की जा सके।

शिक्षक प्रशिक्षण से सशक्त होगी बच्चों की बुनियादी शिक्षा–संजय शुक्ल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को विद्यालयों में प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से मंगलवार को सदर विकास क्षेत्र स्थित बीआरसी डिलिया में पांच दिवसीय एफएलएन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन डायट प्राचार्य संजय शुक्ल ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम 21 जुलाई से 31 अगस्त तक छह चरणों में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कुल 596 शिक्षक एवं शिक्षामित्र प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। जिसमें नई शिक्षण विधियों, गतिविधि आधारित शिक्षण और बच्चों में भाषा व गणितीय दक्षता विकसित करने के उपायों पर विशेष जोर रहेगा। डायट प्राचार्य ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि एफएलएन प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को उसकी कक्षा के अनुरूप बुनियादी भाषा एवं गणितीय दक्षताओं से सशक्त बनाना है। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को गतिविधि आधारित, बाल–केंद्रित एवं नवाचारी शिक्षण तकनीकों से परिचित कराया जा रहा है, ताकि वे इन्हें कक्षा शिक्षण में प्रभावी ढंग से लागू कर बच्चों के सीखने के स्तर में गुणात्मक सुधार ला सकें। खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार त्रिपाठी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप एफएलएन प्रशिक्षण शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने के साथ–साथ बच्चों की आधारभूत सीखने की क्षमता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डायट प्रवक्ता अलीउद्दीन खान ने कहा कि प्रशिक्षण का वास्तविक उद्देश्य केवल शिक्षकों को प्रशिक्षित करना नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण और आनंददायक शिक्षा पहुंचाना है। एआरपी प्रदीप गुप्ता ने प्रशिक्षण के पांचों दिनों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए प्रशिक्षण की विषयवस्तु और उद्देश्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन सर्वेष्ट मिश्र ने किया।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से एआरपी शैलेश मिश्र, शिव प्रसाद, रुक्मिणी मिश्रा, सर्वेंद्र पाण्डेय, राजेश गिरी आदि उपस्थित रहे।

विष्णुदत्त ओझा की पुण्य तिथि पर रक्तदान शिविर 25 को

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । राष्ट्रवाद के अजेय योद्धा हिन्दुत्व के पुरोधा, जन सरोकारों के प्रति समर्पित विष्णुदत्त ओझा के 15 वीं पुण्य तिथि पर आगामी 25 जुलाई शनिवार को आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पुस्तकालय एवं वाचनालय टाउन क्लब के परिसर में दिन में 11 बजे से रक्तदान शिविर 'रक्तदान एक सामाजिक जिम्मेदारी' विषयक संगोष्ठी और सहभोज का आयोजन किया गया है।

यह जानकारी देते हुये विष्णुदत्त ओझा रक्तदान एवं जन सेवा समिति के संयोजक नन्दीश्वर दत्त ओझा ने बताया कि दिन में 11 बजे से रक्तदान के साथ ही स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये स्मृतियों को साझा किया जायेगा।

विश्व हिन्दू महासंघ का विस्तार: पदाधिकारी घोषित

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । विश्व हिन्दू महासंघ की बैठक मंगलवार को जिला अस्पताल के निकट स्थित शिविर कार्यालय पर जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सांगठनिक विस्तार पर चर्चा के साथ ही एडवोकेट संजीव पाण्डेय को अधिवक्ता प्रकोष्ठ का जिला प्रभारी, शुभम शुक्ल, रंजीत यादव, को जिला मंत्री का दायित्व सौंपा गया।

जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पदाधिकारियों से कहा कि वे हिन्दू हितों की रक्षा के लिये अपने–अपने क्षेत्र में रचनात्मक पहल करें और महासंघ के लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान दें।

बैठक में ज्योति भूषण सिंह, बालकृष्ण सिंह, ज्योति भूषण सिंह सोनार, घनश्याम सिंह विष्ठ, धीरेन्द्र चौहान, नित्यम पाठक, दिव्यांश त्रिपाठी, रमेश शर्मा आदि शामिल रहे।

भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने संविधान, सामाजिक न्याय की मांग को लेकर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने मंगलवार को भारत मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष रामऔतार पासवान और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जिलाध्यक्ष एजाज खान के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से भेजा गया।

ज्ञापन सौंपने के बाद भारत मुक्ति मोर्चा के पूर्वान्चल जोन प्रभारी आर के आरतियन, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी डा. रिफाकत अली, बीएमपी मण्डल अध्यक्ष हृदय गौतम ने कहा कि संविधान, सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता तथा नागरिक समानता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार सकारात्मक हस्तक्षेप करे। देश में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाये जांय और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के कथित ध्वस्तीकरण नोटिस को वापस लिया जाय।

राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में संविधान विरोधी बताए गए कानूनों को निरस्त करने, धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने तथा मॉब लिंचिंग और धार्मिक आधार पर होने वाली हिंसा की घटनाओं पर कठोर कार्रवाई, बेगुनाह बताए गए मुस्लिम युवाओं और उलमा की निष्पक्ष जांच के बाद रिहाई, सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए प्रभावी कानून लागू करने, धार्मिक स्थलों पर कथित हमलों पर रोक लगाने तथा प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 के सख्ती से पालन करने, अनुच्छेद 341(3) से संबंधित प्रावधानों में संशोधन, जाति आधारित जनगणना कराने, विभिन्न आयोगों की लंबित सिफारिशों को लागू करने तथा धार्मिक और सामाजिक महापुरुषों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग भी शामिल है।

ज्ञापन के माध्यम से सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले संगठनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और आवश्यक होने पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई। ज्ञापन में राष्ट्रपति से अनुरोध किया गया है कि वे इन मांगों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करें, जिससे संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और सभी नागरिकों के समान अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान मुख्य रूप से राम सुमेर यादव, सुनील यादव, चन्द्र प्रकाश गौतम , सरिता भारती, दीपक आर्य, सरफराज, इरशाद खान, शमीम आलम, भंते प्रज्ञानंद,जनाब अली, शेर अली, जुबेर अहमद आदि शामिल रहे।

भाकियू ने किसान समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को भेजा 15 सूत्रीय ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष विनोद कुमार चौधरी के नेतृत्व में पदाधिकारियों, किसानों, मजदूरों ने जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को 15 सूत्रीय ज्ञापन भेजा। इसी कड़ी में स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु जिलाधिकारी को सम्बोधित ज्ञापन 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन सौंपने के बाद जिलाध्यक्ष विनोद कुमार चौधरी, पूर्वान्चल अध्यक्ष अनूप चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शोभाराम ठाकुर, प्रदेश सचिव दिवान चन्द पटेल, मण्डल अध्यक्ष जयराम चौधरी, राजेन्द्र चौधरी आदि ने कहा कि सरकार किसान हितों के प्रति गंभीर नहीं है। स्थानीय स्तर पर भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। यदि शीघ्र समस्याओं का समाधान न हुआ तो भाकियू निर्णायक आन्दोलन को बाध्य होगी।

ज्ञापन में किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण भारत के हितों से जुड़े मुद्दों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की गई। भाकियू के नेताओं ने विनोद कुमार चौधरी ने कहा कि संगठन पिछले चार दशकों से किसानों के अधिकारों की लड़ाई लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से लड़ता आ रहा है। वर्तमान समय में खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि

–किसानों की मांगे न मानी गई तो भाकियू ने दिया आन्दोलन की चेतावनी

किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। गन्ना किसानों का भुगतान लंबित है, उर्वरकों की उपलब्धता समय पर नहीं हो पा रही है तथा बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

ज्ञापन में भारत–अमेरिका व्यापार समझौते सहित विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया कि यदि कृषि एवं डेयरी क्षेत्र को पर्याप्त सुरक्षा के बिना विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए खोला गया तो इसका सीधा असर देश के करोड़ों छोटे एवं सीमांत किसानों, दुग्ध उत्पादकों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

भारतीय किसान यूनियन ने अपनी प्रमुख मांगों में सभी फसलों पर स्वामीनाथन आयोग की लागत मूल्य के डेढ गुना फार्मूले के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी, गन्ने का न्यूनतम 500 रुपये प्रति क्विंटल राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी), लंबित गन्ना भुगतान ब्याज सहित कराने, किसानों एवं कृषि मजदूरों की संपूर्ण ऋणमाफी, कृषि कार्य के लिए निःशुल्क बिजली तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग की।

इसके अलावा मनरेगा में 200 दिन रोजगार और 700 रुपये प्रतिदिन मजदूरी, डीएपी–यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा, भूमि अधिग्रहण कानून–2013 का सख्ती से पालन, डेयरी क्षेत्र में विदेशी उत्पादों के अनियंत्रित आयात पर रोक, किसानों के पारंपरिक बीज अधिकारों की रक्षा, कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार तथा प्रभावी एवं न्यायसंगत जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग भी की गई।

भाकियू ने ज्ञापन में कहा है कि कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है। यदि किसानों की समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो इसका व्यापक असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण समाज पर पड़ेगा। संगठन ने केंद्र सरकार से किसानों के हित में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग किया।

ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से प्रदीप किसान, रमेश चौधरी, शिवमूरत, रामकृष्ण, दीपनरायन, राम प्रताप, हरि प्रसाद, रामचन्दर सिंह, जगदीश प्रसाद, रामपाल सिंह, रामनयन, ब्रम्हदेव, त्रिवेनी चौधरी, आज्ञाराम चौधरी, उदयपाल पटेल, दिलीप चौधरी, सतिराम यादव, तिलकराम, पारसनाथ, सतीश चौधरी, मो. सलीम के साथ ही भाकियू के अनेक पदाधिकारी शामिल रहे।

बारिश में छाता और तिरपाल की बाजारों में बढ़ी मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मानसून की सक्रियता के साथ ही क्षेत्र में हो रही बारिश ने लोगों की दिनचर्या बदल दी है। बारिश शुरू होते ही बाजारों में छाता और तिरपाल की मांग बढ़ गई है। दुकानों पर सुबह से देर शाम तक ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। मुख्यालय से लेकर क्षेत्र के हर्रैया, भानपुर, रूधौली, नगर बाजार, मुंडेरवा आदि चौराहे पर खुली दुकानों पर बारिश के चलते छतरी, तिरपाल की बिक्री तेज हो गई है। किसान, छोटे दुकानदार और आम लोग जरूरत के अनुसार छाता और तिरपाल की खरीदारी कर रहे हैं।

ब्राह्मण महासभा की बैठक में एकजुटता, पारदर्शिता पर जोर

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । ब्राह्मण महासभा परिसर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में ब्राह्मण महासभा कार्यकारिणी की मासिक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में पिछले कार्यक्रम की समीक्षा की गई। अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ल ने कहा कि ब्राह्मण महासभा से बड़ी संख्या में ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, ब्राह्मणों के सामाजिक उत्थान के लिए जो भी आवश्यक होगा उस कार्य को किया जाएगा श्री शुक्ल ने पदाधिकारियों आवश्यक दिशा–निर्देश देते हुए कहा कि संगठन में पारदर्शिता आवश्यक है सभी पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहना चाहिए । कहा कि जिन्हें भी ब्राह्मण महासभा से सम्बंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो उन्हें मुझसे व्यक्तिगत सम्पर्क करना चाहिए।

राष्ट्रीय महामंत्री शम्भू नाथ मिश्र ने कहा कि ब्राह्मण महासभा में अभी तक पूरी पारदर्शिता के साथ निर्माण कार्य करवाया गया निर्माण समिति द्वारा आय व्यय का विवरण प्रत्येक बैठक में निरन्तर सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्य नारायण शुक्ल सत्ते ने कहा कि ब्राह्मण महासभा एक सामाजिक संगठन है मन्दिर निर्माण के साथ सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमो के लिए समर्पित है जिन्हें राजनीति करना हो उन्हें राजनीतिक दलों में सम्भावना तलासनी चाहिए।

-दायित्वों के प्रति सजग रहें पदाधिकारी- अशोक कुमार शुक्ल

संयुक्त मंत्री विजय बिहारी तिवारी ने कहा कि शोसल मिडिया पर स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए यदि किसी कोई आपत्ति है तो वह आपत्ति सम्बंधित पदाधिकारियों के समक्ष रखना चाहिए।

राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शम्भू नाथ शुक्ल ने कहा कि 2002 से आजतक जितना भी आय–व्यय हुआ है एक एक पैसे का हिसाब मौजूद है सारा हिसाब किताब एकदम पारदर्शी है जिन्हें भी देखना चाहें वह लिखित रुप से प्राप्त कर सकता है।

राष्ट्रीय संगठन मंत्री डा0 वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने कहा कि ब्राह्मणों की एकजुटता और आपसी संवाद निरन्तर होना चाहिए, संवादहीनता तमाम गलतफहमियों का कारण बन जाता है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत पाण्डेय के इस्तीफे पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधेश्याम पाण्डेय, जिलाध्यक्ष नवीन दूबे, महामंत्री संजय शुक्ला, जिला मिडिया प्रभारी सौरभ दूबे, जिला उपाध्यक्ष उपेन्द्र शुक्ल, जिला मंत्री विनय त्रिपाठी, आकाश पाण्डेय, आलोक मिश्रा अनुराग शुक्ल, राकेश कुमार पाण्डेय, वृहस्पति मणि त्रिपाठी, अंकित पाण्डेय, दिनेश तिवारी, विवेक मिश्र आदि उपस्थित रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स

दैनिक भारतीय बस्ती
बस्ती 22 जुलाई 2026 बुधवार

सम्पादकीय

छात्रों का आन्दोलन और सरकार

दिल्ली के जंतर–मंतर पर जो तस्वीर बनी, वह महज एक विरोध प्रदर्शन की तस्वीर नहीं थी। संसद से जंतर–मंतर तक हाथों में तख्तियां लेकर बढ़ते समाजवादी पार्टी के सांसद, पुलिस कार्रवाई से परेशान युवाओं के बीच बैठी डिंपल यादव, सरकार पर सीधे सवाल उठाती इकरा हसन और आक्रामक तेवरों में नजर आतीं प्रिया सरोज इन तीन चेहरों ने उत्तर प्रदेश की 2027 की राजनीति की एक संभावित तस्वीर जरूर सामने रख दी है। सवाल यह नहीं है कि प्रदर्शन में कौन शामिल हुआ। असली सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अब अपनी राजनीति को तीन अलग–अलग महिला चेहरों के जरिए नई सामाजिक और भौगोलिक जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है?सोमवार को नीट परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र और युवा जुटे थे। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रदर्शनकारियों ने सरकार से परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और युवाओं के सवालों पर संवाद की मांग की। इसी प्रदर्शन के समर्थन में समाजवादी पार्टी के सांसद संसद परिसर से जंतर–मंतर की ओर मार्च करते हुए पहुंचे। डिंपल यादव के साथ इकरा हसन और प्रिया सरोज की मौजूदगी ने इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रूप से और ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। डिंपल यादव ने छात्रों के सवालों का समर्थन किया और कहा कि युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए। प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरों में वह आंदोलनकारियों के बीच दिखाई दीं।

यही तस्वीरें अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में पढ़ी जा रही हैं। वजह साफ है। 2027 का विधानसभा चुनाव अब दूर की बात नहीं है। चुनाव आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव फरवरी–मार्च 2027 में तय समय पर होने हैं। राज्य में 403 विधानसभा सीटें हैं और इस चुनाव का असर सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करेगा।समाजवादी पार्टी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव एक बड़ा राजनीतिक मोड़ था। पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 37 पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी 33 सीटों पर रह गई और कांग्रेस को 6 सीटें मिलीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटें जीती थीं और समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर रही थी। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव ने राज्य की राजनीतिक जमीन पर विपक्ष के लिए नई संभावनाएं पैदा कर दीं। अब अखिलेश यादव की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोकसभा चुनाव में बने सामाजिक गठजोड़ को 403 विधानसभा सीटों तक कैसे पहुंचाया जाए।यहीं डिंपल यादव की भूमिका सबसे पहले सामने आती है। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव अब सिर्फ यादव परिवार की राजनीतिक विरासत से जुड़ा चेहरा नहीं रह गई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मैनपुरी सीट पर 2,21,639 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। यह जीत बताती है कि उनका व्यक्तिगत राजनीतिक प्रभाव लगातार मजबूत हुआ है। उनका अंदाज अखिलेश यादव की आक्रामक राजनीति से अलग है। वह तीखे भाषणों की जगह संयमित भाषा, महिला मुद्दों और संवेदनशील राजनीतिक छवि के जरिए अपनी जगह बनाती हैं।

बीजेपी की राजनीति में महिला मतदाताओं का महत्व पिछले एक दशक में लगातार बढ़ा है। उज्ज्वला, आवास, शौचालय, राशन और कानून–व्यवस्था जैसे मुद्दों के जरिए बीजेपी ने महिलाओं के बीच एक मजबूत राजनीतिक आधार बनाया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह महिला मतदाताओं तक अपनी सीधी पहुंच बनाए। डिंपल यादव इस चुनौती का जवाब बन सकती हैं। उनके पास पार्टी का पारंपरिक आधार है, लेकिन उनकी छवि उस आधार से आगे जाने की क्षमता भी रखती है।दूसरा चेहरा इकरा हसन का है। कैराना से लोकसभा पहुंचीं इकरा हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग तरह की आवाज बनकर उभरी हैं। उनका राजनीतिक अंदाज सीधे सवाल पूछने वाला है। पश्चिमी यूपी में किसान, युवा, शिक्षा, रोजगार और अल्पसंख्यक राजनीति एक–दूसरे से अलग नहीं हैं। यहां कोई भी राजनीतिक चेहरा तभी मजबूत होता है, जब वह स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय बहस से जोड़ सके। इकरा हसन के सामने यही अवसर है।उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी युवा पहचान है। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव उस पीढ़ी के बीच लड़ा जाएगा, जिसके लिए सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाएं जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा हैं। नीट विवाद, पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवालों ने युवाओं के बीच बेचौनी पैदा की है। जंतर–मंतर का प्रदर्शन इसी असंतोष को राजनीतिक आवाज देने की कोशिश था। ऐसे मुद्दों पर इकरा हसन जैसे चेहरे सीधे युवाओं से जुड़ सकते हैं।

तीसरा चेहरा प्रिया सरोज का है। मछलीशहर से सांसद प्रिया सरोज 18वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसदों में शामिल हैं। पीआरएस इंडिया के अनुसार उनकी उम्र 27 वर्ष है और लोकसभा में उनकी उपस्थिति 97 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह आंकड़ा उनके संसदीय कामकाज को लेकर उनकी सक्रियता दिखाता है। वह सिर्फ युवा चेहरा नहीं हैं, बल्कि पूर्वांचल के उस सामाजिक और राजनीतिक भूगोल से आती हैं, जहां जातीय प्रतिनिधित्व आज भी चुनावी समीकरणों का सबसे बड़ा आधार है।अखिलेश यादव का पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की राजनीति का केंद्रीय संदेश बना। लेकिन कोई भी राजनीतिक फॉर्मूला केवल नारों से जमीन पर मजबूत नहीं होता। उसके लिए चेहरे चाहिए। डिंपल यादव महिला और पिछड़े वर्गों के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ा सकती हैं। इकरा हसन अल्पसंख्यक और युवा राजनीति की आवाज बन सकती हैं। प्रिया सरोज वंचित और दलित–पिछड़े सामाजिक समूहों के बीच पार्टी की नई पीढ़ी का चेहरा बन सकती हैं। यही इस तिकड़ी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। यह सिर्फ तीन सांसदों का साथ नहीं है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल को जोड़ने वाली संभावित राजनीतिक रेखा है। डिंपल के पास अनुभव और स्वीकार्यता है। इकरा के पास बेबाकी और युवा ऊर्जा है। प्रिया के पास नई पीढ़ी की राजनीतिक पहचान है। अगर सपा इन तीनों चेहरों को अलग–अलग क्षेत्रों में लगातार सक्रिय करती है, तो यह प्रयोग पार्टी के लिए चुनावी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।

हालांकि बीजेपी के लिए चुनौती को केवल इन तीन महिला सांसदों की लोकप्रियता से जोड़ना जल्दबाजी होगी। राजनीति में वायरल तस्वीरें वोट में तभी बदलती हैं, जब उनके पीछे संगठन खड़ा हो। 2024 में समाजवादी पार्टी की सफलता के बावजूद 2027 का विधानसभा चुनाव पूरी तरह अलग होगा। लोकसभा चुनाव में मुद्दों का प्रभाव व्यापक होता है, जबकि विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर की मशीनरी, स्थानीय उम्मीदवार और जातीय समीकरण निर्णायक होते हैं। सपा को यह साबित करना होगा कि डिंपल, इकरा और प्रिया की लोकप्रियता सिर्फ संसद और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है।

समुद्र को जीतकर बनी मुंबई की अद्भुत विकास गाथा

—अखिल कुमार यादव—

भारत की आर्थिक राजधानी, सपनों का शहर, मायानगरी और अवसरों की धरतीकृमुंबई को अनेक नामों से जाना जाता है। यह वह शहर है जहाँ हर दिन लाखों लोग अपने सपनों को साकार करने की आशा लेकर आते हैं। ऊँची–ऊँची इमारतें, समुद्र के किनारे फैला मरीन ड्राइव, विश्वप्रसिद्ध बॉलीवुड, देश का सबसे बड़ा शेयर बाजार, विशाल बंदरगाह और चौबीसों घंटे गतिशील जीवन, ये सब मिलकर आधुनिक मुंबई की पहचान बनाते हैं। किंतु इस महानगर का इतिहास उतना ही रोमांचक है जितना इसका वर्तमान। आज जिस शहर को हम मुंबई के नाम से जानते हैं, वह कभी समुद्र में बिखरे सात छोटे–छोटे द्वीपों का समूह था। मानव की अद्भुत इंजीनियरिंग क्षमता, दूरदर्शी योजनाओं और व्यापारिक दृष्टिकोण ने इन द्वीपों को जोड़कर विश्व के सबसे प्रभावशाली महानगरों में बदल दिया। लगभग दो हजार वर्ष पूर्व यह क्षेत्र समुद्र से घिरे सात अलग–अलग द्वीपों के रूप में अस्तित्व में था। इन द्वीपों के नाम थेकृबॉम्बे (मुंबई द्वीप), कोलाबा, ओल्ड वूमन आइलैंड (लिटिल कोलाबा), माहीम, मझगांव, परेल और वरली। इनके बीच समुद्री जल, दलदली क्षेत्र और ज्वार–भाटा का प्रभाव रहता था। एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाने का एकमात्र साधन नाव थी। आज जहाँ चौड़ी सड़कें, रेलमार्ग और मेट्रो नेटवर्क दिखाई देते हैं, वहाँ कभी समुद्र की लहरें उठती थीं।

मुंबई का इतिहास केवल भूगोल का इतिहास नहीं, बल्कि सभ्यताओं और संस्कृतियों के विकास का भी इतिहास है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अधीन रहा। इसके बाद सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट और सिल्हारा जैसे राजवंशों ने यहाँ शासन किया। समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण यह क्षेत्र प्रारंभ से ही व्यापार और समुद्री गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। अरब व्यापारियों के जहाज यहाँ आते–जाते थे और धीरे–धीरे यह क्षेत्र पश्चिमी भारत के समुद्री व्यापार का प्रमुख पड़ाव बन गया। मध्यकाल में यह क्षेत्र गुजरात सल्तनत के अधीन आया। सन् 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने एक संधि के तहत इन द्वीपों को पुर्तगालियों को सौंप दिया। पुर्तगालियों ने यहाँ चर्चों का निर्माण कराया, समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया और कई छोटे किलों की स्थापना की। उन्होंने इस प्राकृतिक बंदरगाह की सामरिक और आर्थिक महत्ता को अच्छी तरह समझ लिया था। मुंबई के इतिहास का सबसे रोचक अध्याय सन् 1661 में शुरू हुआ, जब पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ। विवाह के दहेज में ये द्वीप अंग्रेजों को सौंप दिए गए। कुछ वर्षों बाद 1668 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को वार्षिक किराये पर दे दिया। यहीं से आधुनिक मुंबई के निर्माण की वास्तविक शुरुआत हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने समझ लिया था कि यदि इन बिखरे द्वीपों को जोड़ दिया जाए तो यह स्थान एशिया के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में बदल सकता है।

18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेज इंजीनियरों ने समुद्र के साथ एक अभूतपूर्व संघर्ष आरंभ किया। उन्होंने दलदली क्षेत्रों और समुद्र के उथले हिस्सों को मिट्टी, पत्थरों और मलबे से भरना शुरू किया। इस प्रक्रिया को भूमि पुनरुद्धार (स्ंदक त्मबसंउ. जपवद) कहा जाता है। यह केवल भूमि निर्माण की परियोजना नहीं थी, बल्कि प्रकृति की चुनौतियों पर मानव की तकनीकी क्षमता का अद्भुत उदाहरण भी थी। इस दिशा में हॉर्नबी वेलार्ड परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इस परियोजना के माध्यम से वरली और माहीम के बीच समुद्री जल के अनियंत्रित प्रवेश को रोका गया। इसके बाद कोलाबा कॉजवे, बैक बे रिक्लेमेशन और अन्य निर्माण कार्यों ने धीरे–धीरे सातों द्वीपों को एक विशाल भूभाग में बदल दिया। आज का अधिकांश दक्षिण मुंबई क्षेत्र इसी भूमि पुनर्ग्रहण का परिणाम है। यदि प्राकृतिक बंदरगाह न होता, तो शायद मुंबई कभी इतना बड़ा व्यापारिक केंद्र नहीं बन पाती। इसकी गहरी और सुरक्षित खाड़ी ने बड़े–बड़े जहाजों को आश्रय दिया। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच समुद्री व्यापार के विस्तार के साथ मुंबई का महत्व तेजी से बढ़ा। 1869 में स्वेज नहर खुलने के बाद यूरोप और भारत के बीच समुद्री दूरी काफी कम हो गई, जिससे मुंबई का बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख द्वार बन गया। कपास, मसाले, अफीम, वस्त्र और अन्य उत्पादों का निर्यात यहाँ से बड़े पैमाने पर होने लगा।

औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से मुंबई में कपड़ा मिलों की स्थापना हुई। धीरे–धीरे यह भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर बन गया। लाखों श्रमिक रोजगार की तलाश में देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ आने लगे। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान और देश के अनेक हिस्सों के लोग यहाँ बसते चले गए। यही कारण है कि मुंबई आज भारत का सबसे बहुसांस्कृतिक शहर माना जाता है, जहाँ लगभग हर भाषा, हर धर्म और हर संस्कृति के लोग साथ रहते हैं। भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी भी मुंबई से ही चली। 16 अप्रैल, 1853 को बोरीबंदर (आज का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस) से ठाणे तक चली इस रेल ने देश में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की शुरुआत की। यह घटना केवल रेलवे का इतिहास नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के औद्योगिक विकास की भी आधारशिला थी। मुंबई की पहचान केवल व्यापार तक सीमित नहीं रही। 20वीं शताब्दी में यहाँ फिल्म उद्योग का विकास हुआ और बॉलीवुड विश्व के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में शामिल हो गया। लाखों कलाकार, लेखक, संगीतकार और तकनीशियन अपने सपनों को लेकर मुंबई पहुँचे। इसने शहर को 'सपनों की नगरी' की पहचान दिलाई।

मुंबई का सांस्कृतिक जीवन भी अत्यंत समृद्ध है। यहाँ के मूल निवासी कोली समुदाय ने सदियों से समुद्र और मत्स्य व्यवसाय के माध्यम से इस क्षेत्र की पहचान बनाए रखी। आज भी कोली संस्कृति, उनके उत्सव और पारंपरिक जीवनशैली मुंबई की विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसी प्रकार पारसी समुदाय ने उद्योग, शिक्षा और समाजसेवा में उल्लेखनीय योगदान दिया। टाटा, वाडिया और गोदरेज जैसे उद्योग समूहों ने मुंबई को आर्थिक शक्ति प्रदान की। मराठी, गुजराती, सिंधी, दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय समुदायों ने भी इस शहर के विकास में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। मुंबई की सांस्कृतिक धरोहरों में गेटवे ऑफ इंडिया, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, एलीफेंटा गुफाएँ, हाजी अली दरगाह, सिद्धिविनायक मंदिर, मरीन ड्राइव और छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय जैसे अनेक स्थल शामिल हैं। इनमें से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और एलीफेंटा गुफाएँ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल हैं। ये स्मारक केवल स्थापत्य कला के उदाहरण नहीं, बल्कि मुंबई की ऐतिहासिक यात्रा के साक्षी भी हैं।

'बॉम्बे' से 'मुंबई' बनने की कहानी भी इस शहर की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि 'Bombay' नाम पुर्तगाली शब्द Bom Bahia अर्थात 'अच्छी खाड़ी' से विकसित हुआ। दूसरी ओर 'मुंबई' नाम स्थानीय आराध्य देवी मुंबा देवी से जुड़ा है। वर्ष 1995 में महाराष्ट्र सरकार ने शहर का आधिकारिक नाम बॉम्बे से बदलकर मुंबई कर दिया, जिससे इसकी स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को अधिक सम्मान मिला। आज मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है। भारतीय रिजर्व बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अनेक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यालय, देश के सबसे बड़े मीडिया संस्थान तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक प्रतिष्ठान यहीं स्थित हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में मुंबई का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे देश की आर्थिक धड़कन कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी।

हालाँकि विकास की इस तेज रफ्तार के साथ अनेक चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। भूमि पुनर्ग्रहण और अनियोजित शहरीकरण के कारण मैंग्रोव वनों का क्षरण हुआ है। समुद्र स्तर में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ एवं जलभराव जैसी समस्याएँ लगातार बढ़ रही हैं। 2005 की भीषण बाढ़ ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्राकृतिक जल निकासी तंत्र की अनदेखी कितनी महँगी पड़ सकती है। इसलिए आधुनिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित रखना भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए आज मुंबई में अनेक आधुनिक परियोजनाएँ चल रही हैं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (अटल सेतु), कोस्टल रोड परियोजना, विस्तृत मेट्रो नेटवर्क और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसे प्रकल्प शहर के भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बढ़ती आबादी, यातायात और आर्थिक गतिविधियों के अनुरूप आधुनिक बुनियादी ढाँचा तैयार करना है।मुंबई का इतिहास हमें यह सिखाता है कि दूरदृष्टि, तकनीकी नवाचार और सामूहिक प्रयास असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को भी संभव बना सकते हैं। समुद्र में बिखरे सात छोटे द्वीपों से विश्वस्तरीय महानगर बनने तक की यह यात्रा केवल इंजीनियरिंग की उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवीय साहस, परिश्रम, उद्यमिता और विविधता की भी प्रेरक गाथा है। आज जब कोई व्यक्ति मरीन ड्राइव पर खड़े होकर अरब सागर की लहरों को देखता है, तो शायद उसे यह एहसास नहीं होता कि जिस धरती पर वह खड़ा है, उसका बड़ा हिस्सा कभी समुद्र का हिस्सा था। यही मुंबई की सबसे बड़ी विशेषता हैकृयह शहर केवल इमारतों, सड़कों और उद्योगों का समूह नहीं, बल्कि इतिहास, संघर्ष, विज्ञान, संस्कृति और अनगिनत सपनों से निर्मित वह जीवंत महानगर है जिसने सचमुच समुद्र को चुनौती देकर अपने लिए नई पहचान गढ़ी है।

छात्र आन्दोलन के दीर्घकालीन होने का निहितार्थ

—मनोज कुमार झा—

सीजेपी के संसद मार्च के दौरान बलप्रयोग हुआ, जो ऐसे आंदोलनों के मजबूत व टिकाऊ होने का सबूत माना जाता है। इसके अगुआ सोनम वांगचुक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बावजूद आंदोलन कमजोर नहीं हुआ। बेरोजगारी, शिक्षा, असमानता और लोकतंत्र से जुड़ी चिंताओं ने इसे व्यापक समर्थन दिलाया है। जब 'कॉकरोच जनता पार्टी' आंदोलनकारियों ने संसद की ओर कूच किया, तो सत्ता के नशे में चूर सरकार ने – जो किसी भी किस्म का विरोध सहना तो एक तरफ, असहमति तक बर्दाश्त नहीं करती–अपने अहंकार में उन युवाओं पर हाथ उठवाया जिन्होंने सिर्फ उपवास किया था, धरना दिया और अपनी बात रखी थी। आज दोपहर हुई धक्का–मुक्की, लाठीचार्ज, खून बहना और आंसू गैस के दृश्य भुलाना मुश्किल होगा। यह उस घटनाक्रम का नतीजा था जो शनिवार सुबह, 18 जुलाई को शुरू हुआ था, जब इस आंदोलन से जुड़े सबसे जाने–माने चेहरों में से एक, सोनम वांगचुक को पुलिस ने बेहद कमजोर व बेबुनियाद कारणों के आधार पर वहां से हटाया। शनिवार और रविवार को, उनकी गैर–मौजूदगी में भी जंतर–मंतर पर विरोध प्रदर्शन अनवरत जारी रहा।

तथापि, अगर इस हिंसा के पीछे मकसद आंदोलन को तोड़ना था, तो पिछले कुछ दिनों ने इसके उलट साबित कर दिखाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आंदोलन किसने शुरू किया, अब इसका नेतृत्व कौन कर रहा, या वहां मौजूद सभी हर मुद्दे पर सहमत हैं या नहीं। मायने यह रखता है कि युवाओं ने इतनी बड़ी संख्या में आकर सामूहिक रोष जताया। यह किसी एक चेहरे, नाम या पार्टी से कहीं बड़ी बात है। अपनेआप में लोकतंत्र की जबरदस्त लहर है। मैंने अपने सामने यह होते देखा, पहले शनिवार को और फिर आज। मैं 18 जुलाई को जंतर–मंतर पर उपवासरत छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने गया था। पहले इसलिए नहीं जा सका कि दिल्ली से बाहर, अपने गृह राज्य में कुछ जरूरी और न टाली जा सकने वाली प्रतिबद्धताओं में व्यस्त था। जब उस सुबह सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने की खबर मिली, तो कुछ पल के लिए सोचा कि क्या ऐसे समय में विरोध स्थल पर जाना उचित होगा। मैंने सोचा कि अवश्य ही माहौल मायूसी भरा होगा। फिर खुद को याद दिलाया कि एकजुटता दिखाने का असली औचित्य तो तभी है, जब आंदोलन को डराने या हौसला तोड़ने की कोशिश की जा रही हो।

जंतर–मंतर पर मैंने जो देखा, वह मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग था। मायूसी और थकावट के बजाय, दृढ़ संकल्प और हिम्मत व्याप्त देखी। माहौल आशा, नैतिक विश्वास और सामूहिक मकसद के असाधारण भाव से लबरेज था। ये सब युवा कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले इकट्ठा थे, ऐसा नाम जो विद्रोह दर्शाता है। जब तंत्र के सबसे ऊंचे ओहदों में से एक की ओर से देश के बेरोजगार युवाओं की तुलना के लिए कॉकरोच जैसे अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया, तो युवाओं ने इस ताने को बतौर पहचान अपना लिया।

सामाजिक आंदोलनों के समाजशास्त्र का अध्ययन करने, पढ़ाने और उनमें शामिल होने के पीछे मनोस्थिति का अध्ययन दशकों तक करने के बाद, मैं इस विरोध का विश्लेषण अकादमिक और राजनीतिक, दोनों नजरियों से किए बिना नहीं रह सकाय क्योंकि इसमें वे कई खूबियां थीं जिसकी तलाश श्नव सामाजिक आंदोलनों्श के सिद्धांतकार लोकतांत्रिक संघर्षों में करते हैं। सिर्फ लिखित सामग्री बांटने वाले या वर्ग–हितों के आधार पर होने वाले पारंपरिक आंदोलनों के उलट, यह जनांदोलन लोकतंत्र की जगह, संवैधानिक नैतिकता व नागरिकता की गरिमा बहाल करने के बारे में भी उतना ही था। एलेन टुरेन का तर्क कि ऐसे आंदोलन समाज की दिशा तय करने के लिए आखिरी उपाय होते हैं–यानी उन मूल्यों को परिभाषित करना,जिनके साथ लोग जीना चाहते हैं–यह मुहिम ठीक उसे परिभाषित करती लगी जो ये युवा हासिल करना चाह रहे यअल्बर्टो मेलुची की अंतर्दृष्टि कि ऐसे अवसरों पर ताकत संगठनात्मक पदानुक्रम के बजाय सामूहिक पहचान व साझा अर्थों से चालित होती है,वह यहां साफ दिखी कि कैसे अजनबी लोग एक साझे मकसद हेतु साथी बन गए।

राम मंदिर विवाद की आंच के बीच बीजेपी

—अजय कुमार—

अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ा रखा है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार और बीजेपी को घेरने की तैयारी में है, जांच की दिशा और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं और मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 27 जुलाई को होनी है, जबकि राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए नई विशेष जांच टीम गठित करने का फैसला किया है। राजनीतिक रूप से यह विवाद बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन पार्टी ने इस पूरे माहौल का जवाब किसी नए राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप से देने के बजाय अपना ध्यान सीधे संगठन पर केंद्रित करने का फैसला किया है। बीजेपी अब राम मंदिर चढ़ावा विवाद की राजनीतिक गर्मी से आगे निकलकर 2027 के विधानसभा चुनाव की असली जमीन तैयार करने में जुट गई है बूथ।22 जुलाई को उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों में एक साथ बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। यह तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार इतने बड़े स्तर पर पार्टी अपने बूथ नेटवर्क को एक साथ परखने जा रही है। बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में करीब 1.62 लाख बूथ अध्यक्ष हैं। इन्हीं बूथों को पार्टी अपनी चुनावी मशीनरी की सबसे निचली, लेकिन सबसे निर्णायक इकाई मानती है। सम्मेलन में केवल भाषण नहीं होंगे, बल्कि बूथ अध्यक्षों की मौजूदगी, उनके कामकाज और चुनावी तैयारियों का वास्तविक परीक्षण किया जाएगा। यानी 22 जुलाई को बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं जुटा रही है, बल्कि अपने संगठन की जमीनी हालत का हिसाब लेने जा रही है। पार्टी ने बूथ अध्यक्षों को उनके बूथ नंबर के हिसाब से बैठाने की व्यवस्था की है। कुर्सियों पर नाम की जगह बूथ नंबर दर्ज होगा। मंच से किसी भी बूथ अध्यक्ष को अचानक बुलाया जा सकता है और उससे उसके बूथ से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। पार्टी यह जानना चाहती है कि जिस व्यक्ति के हाथ में बूथ की जिम्मेदारी है, क्या वह वास्तव में अपने इलाके के मतदाताओं, कार्यकर्ताओं और चुनावी समीकरण से परिचित है। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन बीजेपी की तैयारी चुनावी साल के इंतजार पर निर्भर नहीं रहना चाहती। पार्टी की रणनीति साफ है पहले बूथ को मजबूत करो, फिर विधानसभा क्षेत्र की चुनावी रणनीति तैयार करो। जहां बूथ अध्यक्ष सक्रिय हैं, वहां संगठन को और मजबूत किया जाएगा। जहां निष्क्रियता या कमजोरी मिलेगी, वहां सुधार, जिम्मेदारी में बदलाव या नए कार्यकर्ताओं को आगे लाने पर विचार किया जा सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के हालिया उत्तर प्रदेश दौरे के बाद पार्टी के इस संगठनात्मक अभियान को और गति मिली है। जुलाई की शुरुआत में लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच नबीन ने राम मंदिर चढ़ावे के विवाद को लेकर विपक्ष पर हमला बोला था। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों पर धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर, अखिलेश यादव ने नितिन नबीन के उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर राजनीतिक तंज किया। इस तरह विवाद का राजनीतिक असर साफ दिखाई देने लगा था।लेकिन बीजेपी अब इस मुद्दे को अपनी चुनावी रणनीति का स्थायी केंद्र नहीं बनाना चाहती। पार्टी को पता है कि अगर चुनावी राजनीति लगातार आरोप–प्रत्यारोप के इर्द–गिर्द घूमती रही तो संगठनात्मक तैयारी पीछे छूट सकती है। यही वजह है कि पार्टी ने राजनीतिक नैरेटिव को विवाद से संगठन की ओर मोड़ने की कोशिश शुरू की है। संदेश यह है कि जांच और राजनीतिक बहस अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन चुनावी तैयारी रुकने वाली नहीं है।

भारतीय बस्ती को शुभकामनाएं

आज भारतीय बस्ती का है अड़तालीसवाँ वर्ष ।
इस अवसर पर मन में होता "वर्मा" कितना हर्ष ।
कभी किसी के सम्मुख करिये "वर्मा" मत फरियाद ।
यह पुनीत दिन आया कितने संघर्षों के बाद ।
करते हैं जो घोर साधना वह अम्बर को छूते ।
हुआ भारतीय बस्ती पुष्पित मेहनत के बलबूते ।
स्व०दिनेश पाण्डेय जी ने जीवन में कभी न मानी हार
इस अवसर पर नमन करता "वर्मा" शत शतबार ।
प्रदीप पाण्डेय जी ने गति दी है निज प्रतिभा से आज
भारतीय बस्ती करता है, इनके ऊपर नाज ।
भारतीय बस्ती यह निशदिन फूले और फले ।
यही कामना आंधी में भी दीपक सदा जले ।

(वी.के वर्मा)
वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक
बस्ती।

352 करोड़ की 70 परियोजनाओं का तोहफा देकर बोले मुख्यमंत्री बहराइच अब पिछड़ा नहीं, विकास की नई पहचान

संवाददाता—बहराइच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को महसी विधानसभा क्षेत्र के तेजवापुर स्थित बेड़नपुर रामलीला मैदान से बहराइच को 352 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 70 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए कहा कि बहराइच अब आकांक्षी जनपद नहीं, बल्कि विकास की नई पहचान बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला तथा महाराजा सुहेलदेव के सम्मान, सुशासन और कानून व्यवस्था को प्रमुख मुद्दा बनाया। कहा कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों की जगह जेल या जहन्नुम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले बहराइच भू—माफिया और अवैध गतिविधियों के कारण बदनाम था लेकिन आज जिले की पहचान तेजी से बदल रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने महाराजा सुहेलदेव को वह सम्मान दिलाया, जो पूर्ववर्ती सरकारें नहीं दे सकीं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी के नाम पर मेले को बढ़ावा दिया, जबकि उनकी सरकार ने इस पर रोक लगाकर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर भव्य स्मारक और मेडिकल कॉलेज स्थापित कराया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाराबंकी—बहराइच फोरलेन परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने दावा किया कि कृषि के क्षेत्र में बहराइच देश में दूसरे और शिक्षा के क्षेत्र में चौथे स्थान पर पहुंचा है। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को इंटरमीडिएट तक अपग्रेड करने, भरतपुर में विस्थापित परिवारों के लिए आवासीय कॉलोनी तथा अन्य विकास योजनाओं का भी उल्लेख किया।

समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले किसान आत्महत्या करने को मजबूर था, कानून व्यवस्था चरमरा गई थी और भ्रष्टाचार विकास पर भारी था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार बिना जाति और तुष्टीकरण के सुशासन के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों की जगह जेल या जहन्नुम है,

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने जिले में मगरमच्छ और तेंदुए के हमलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने वन विभाग और प्रशासन को जंगल से सटे गांवों में गश्त बढ़ाने, बिना दरवाजे वाले घरों में दरवाजे लगवाने तथा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को वन्यजीवों के प्रति जागरुक करने के निर्देश दिए, ताकि जनहानि रोकी जा सके। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल, आईजी अशोक शुक्ला, जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने व्यवस्थाओं की निगरानी की। जनसभा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोग मौजूद रहे।

जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण पर पुर्नविचार के लिए राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

संवाददाता—महराजगंज। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण को रोकने पर पुनर्विचार किए जाने की मांग को लेकर आल इंडिया मुजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को दिया। विश्वविद्यालय के संबंध में जारी ध्वस्तीकरण नोटिस को लेकर चिंता जताते हुए निष्पक्ष व विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की गई।

पदाधिकारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल एक भवन नहीं, बल्कि शिक्षा, शोध, सामाजिक प्रगति व विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र होता है। यदि विश्वविद्यालय से संबंधित कोई कानूनी, प्रशासनिक अथवा नियामकीय विवाद है तो उसका समाधान विधि सम्मत प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए।

ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों की शिक्षा, शिक्षकों एवं कर्मचारियों का भविष्य तथा शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के विरुद्ध प्रस्तावित ध्वस्तीकरण संबंधी कार्रवाई पर तत्काल पुनर्विचार किया जाए। मामले की निष्पक्ष व पारदर्शी समीक्षा कराने के साथ ही विद्यार्थियों, शिक्षकों व कर्मचारियों के शैक्षणिक भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस दौरान जिलाध्यक्ष सरवर खान, रुहुल्ला खान, जियाउल खान, वसी अहमद, सफी अहमद, मोहिउद्दीन, नूर आलम, मो. जमालुद्दीन, आफताब आलम आदि मौजूद रहे।

योगी बोले— हमने छांगुर को जेल में ठूंसा, नौकरी आते ही चचा—भतीजे निकल पड़ते थे, 396 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी

संवाददाता—श्रावस्ती। बहराइच के बाद सीएम श्रावस्ती पहुंचे। यहां सीताद्वार में 396 करोड़ से अधिक की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने कहा—छांगुर को हम लोगों ने बलरामपुर में पकड़ा था। वो कैसे बेवकूफ बनाकर कालनेमी के रूप में रहता था। पकड़कर उसे जेल के अंदर ठूंसा है। उसके जो अनैतिक काम हो रहे थे, उनपर बुलडोजर चल चुका है। छांगुर और उसके गुर्गे धराशायी हो चुके हैं। हमने कहा था कि कोई बेटी—व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाए गा तो उसकी जगह जेल या जहन्नुम में होगी। आज यही तो हो रहा है।

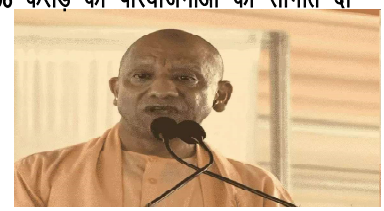

श्रावस्ती में योगी ने जनता का अभिवादन किया। सीएम ने आगे कहा कि भिनगा में भाजपा का विधायक होता तो श्रावस्ती में और बड़ी योजनाएं आतीं। ये सपा वालों को विकास की पैरवी करने की फुर्सत कहां है। इनके लूट खसोट के अवैध धंधे सरकार पहले ही चौपट कर चुकी है। अब ये दुम दबाकर छिपे रहते हैं। क्योंकि इनको पता है कि गलत का परिणाम गलत होगा। जो विकास श्रावस्ती का होना चाहिया वो नहीं हुआ। 75 साल तक श्रावस्ती रेलवे लाइन से दूर रहा। जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो यहां रेलवे लाइव पहुंची है। आज यहां एयरपोर्ट भी बन रहा है। अयोध्या की तर्ज पर श्रावस्ती का विकास किया जाएगा। श्रावस्ती को फोर लेन की कनेक्टिविटी से जोड़ने काम कर रहे हैं। विकास के हर बड़े कार्य आज श्रावस्ती में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने श्रावस्ती को पीछे ढकेला देश को 1947 में आजाद हो गया था। आजादी के बाद कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया। लेकिन विकास नहीं किया। बल्कि इस क्षेत्र को पीछे ढकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। न रेल की कनेक्टिविटी थी, न एयर। सड़क को कोई पूछने वाला नहीं था। योगी ने कहा— महाराजा सुहेलदेव के कारण हम लोग जीवित हैं। उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने की बजाए सपा कांग्रेस के लोगों ने विदेशी आक्रांता गाजी के नाम पर मेला लगाना शुरू कर दिया। हमारी सरकार आई तो हमने कहा कोई ऐसा आयोजन करेगा तो कार्रवाई करेंगे। ये स्वतंत्र भारत है। स्वाधीन भारत में विदेशी आक्रांता का सम्मान नहीं हो सकता। ये कांग्रेस और सपा के लोग हैं। इन्हें मां जानकी, भगवान संभवनाथ, भगवान बुद्ध अच्छे नहीं लगते। मां जानकी की रामायणकालीन परंपरा अच्छी नहीं लगती। इन्हें तो गाजी मियां का मेला लगवाना था। इसलिए इनकी दुर्गति भी हुई है। हर जिले में माफिया होता था योगी ने कहा— सपा सरकार में हर जिले में एक माफिया होता था। थाने में एक गुंडे का कब्जा हो जाता था। तहसील में भू माफिया, लैंड—सैंड माफिया पशु माफिया का कब्जा हो जाता था। जनता टकटकी लगाए देखती थी। उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। उसका परिणाम ये हो गया कि यूपी बीमार और श्रावस्ती पिछड़ गया। इस जिले की दुर्गति हो गई। नौकरी आते ही चाचा—भतीजे की जोड़ी निकल पड़ती थी योगी ने कहा— यूपी में 16 करोड़ लोग फ्री में राशन ले रहे हैं। पहले ये राशन बबुआ के गुर्गे खा जाते थे। 65 लाख गरीबों को हमने आवास दिया है। पहले ये पैसा भी माफिया चट कर जाते थे। तीन करोड़ घरों में शौचालय बनवाया है। इसका पैसा भी खा जाते थे। सिलेंडर की बोली लगती थी। आज ये युवाओं को बहका रहे हैं। 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी यूपी में मैंने दी है। कोई सिफारिश या वसूली नहीं होती। पहले नौकरी के विज्ञापन आते ही चाचा—भतीजे की जोड़ी निकल पड़ती थी। सैफई सिंडिकेट का कब्जा होता था। पर्ची पर खर्ची मिलती थी, तब नौकरी मिलती थी। आज चाहे अयोग की नौकरी हो या शिक्षक भर्ती हो या पुलिस की, उसमें श्रावस्ती के युवाओं को नौकरी मिल रही है। अब मच्छर—माफिया का आतंक नहीं है।

बैठक में मेला व्यवस्था, सुरक्षा और सुविधाओं पर हुई चर्चा, संतों ने समन्वय पर दिया जोर

—भारतीय बस्ती संवाददाता— अयोध्या। आगामी नासिक कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर मेला प्रशासन और संत समाज के बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अयोध्या हनुमानगढ़ी से अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता महंत संजय दास सम्मिलित हुए उन्होंने बताया कि बैठक में मेला आयुक्त शेखर सिंह, मेला पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, नगर निगम आयुक्त मनीषा खत्री सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने संतों के साथ कुंभ मेले की व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की। इसके बाद अधिकारियों ने संबंधित स्थलों का निरीक्षण भी किया।बैठक में पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद धर्म सम्राट श्रीमहंत ज्ञानदास महाराज, वैष्णव अनी अखाड़ा के श्रीमहंतगण, निर्वाणी अखाड़ा के श्रीमहंत मुरली दास महाराज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत राजेंद्र दास महाराज, राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत संजय दास महाराज, दिगंबर अनी अखाड़ा के श्रीमहंत वैष्णव दास महाराज, महंत माधव दास महाराज (मौनीजी दिगंबर), महंत मोहन दास महाराज खाकी, महंत भक्तिचरण दास महाराज (नासिक) सहित बड़ी संख्या में संत—महंत उपस्थित रहे।बैठक के दौरान संतों ने कुंभ मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवास, पेयजल, स्वच्छता, यातायात, सुरक्षा, चिकित्सा और अखाड़ों की व्यवस्थाओं से जुड़े विभिन्न सुझाव प्रशासन के समक्ष रखे। अधिकारियों ने संतों को भरोसा दिलाया कि सभी सुझावों पर गंभीरता से अमल करते हुए कुंभ मेले को सुव्यवस्थित एवं दिव्य बनाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत संजय दास महाराज ने कहा कि कुंभ केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का विश्वस्तरीय आयोजन है। उन्होंने कहा कि संत समाज और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय से ही श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रशासन संतों के सुझावों को प्राथमिकता देगा और नासिक कुंभ को ऐतिहासिक एवं भव्य स्वरूप प्रदान करेगा।बैठक के अंत में प्रशासनिक अधिकारियों ने संतों के साथ विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया तथा आवश्यक सुधारों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने का आश्वासन दिया। संतों ने भी कुंभ मेले के सफल आयोजन के लिए प्रशासन को हर संभव सहयोग देने की बात कही।

एसपी शक्ति मोहन ने चलाई मुहिम, मिले देश के कई राज्यों से गायब मोबाइल

संवाददाता—महराजगंज। महराजगंज में देश के कई राज्यों से गायब मोबाइल मिले हैं। इस जिले के तेजतर्रार एसपी शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश पर सर्विलांस सेल ने बड़ी मुहिम चलाई। सीईआईआर पोर्टल और अन्य तकनीकी उपायों के जरिए खोए हुए 110 मोबाइल फोन बरामद कर उनके ओनर्स को सौंपे गए हैं। लौटाए गए मोबाइल फोन की कीमत 35 लाख रुपए आंकी गई है। जिन ओनर्स के मोबाइल फोन लौटाए गए हैं उनमें तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और राजस्थान के लोग शामिल हैं। मंगलवार को महराजगंज के पुलिस ऑफिस में एसपी शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशों पर अमल करते हुए ओनर्स को बुलाकर कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें मोबाइल फोन वापस कर दिए गए। मोबाइल फोन वापस पाकर ओनर्स के चेहरे खिल गए। बरामद फोन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार के लोगों के हैं। पुलिस ऑफिस में एसपी की मौजूदगी में अपने मोबाइल फोन वापस पाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लोगों ने पुलिस के प्रति आभार प्रकट किया।

जिन्हें मोबाइल फोन लौटाए गए हैं वे देश के कई प्रदेशों के हैं। मंगलवार को पुलिस ऑफिस में मोबाइल लौटाए जाने के समय दूर—दराज के जो लोग नहीं आ सके उन्हें कूरियर या अन्य माध्यमों से मोबाइल वापस भेजे जाएंगे। महराजगंज पुलिस इसकी तैयारी कर रही है। ऐसे लोगों के पते पर मोबाइल भेजे जाएंगे। मोबाइल लौटाए जाने से पहले सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इतनी बड़ी संख्या में गायब मोबाइल पकड़े जाने को महराजगंज पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। महराजगंज के एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि पिछले 4 महीने में अब तक 1.25 करोड़ रुपये कीमत के कुल 417 मोबाइल फोन बरामद कर ओनर्स को वापस किए जा चुके हैं। अपना मोबाइल फोन वापस पाकर लोगों ने महराजगंज पुलिस का आभार जताया।

2019 बैच के आईपीएस शक्ति मोहन अवस्थी ने रांची बीआईटी से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। इस साल 31 मार्च को महराजगंज में चार्ज लेने के बाद से एसपी शक्ति मोहन अवस्थी लगातार ऐक्शन मोड हैं। उनकी कार्रवाईयों से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जिले की कानून—व्यवस्था को लेकर एसपी शक्ति मोहन ने सख्त रुख दिखाया है। मोबाइल बरामद करने वाली टीम में शिवानन्द पासवान, मो. कुतुबुद्दीन, राजकुमार राजभर, आलोक पाण्डेय, सुधीर यादव, सूरज गुप्ता औ नीरज गोंड शामिल रहे।

देवीपाटन मंडल डीआईजी ने की अपराध समीक्षा बैठक

संवाददाता—बहराइच। देवीपाटन मंडल के डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला मंगलवार दोपहर बहराइच पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। शाम पांच बजे पुलिस लाइन सभागार में उन्होंने पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी और अन्य अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जनपद की कानून—व्यवस्था, हत्या, लूट, चोरी, नकबजनी, महिला एवं बाल अपराध, साइबर अपराध, लंबित विवेचनाओं और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, प्रभावी अभियोजन, आईजीआरएस, सीएम डैशबोर्ड, सीसीटीएनएस, ई—सम्मन और ई—साक्ष्य जैसी डिजिटल पुलिसिंग व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। डीआईजी ने आगामी सावन मास, कांवड़ यात्रा और अन्य पर्व—त्योहारों के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील स्थलों पर नियमित रूट मार्च एवं फ्लैग मार्च करने, सोशल मीडिया की सतत निगरानी रखने, आयोजकों एवं धर्मगुरुओं के साथ समन्वय स्थापित करने तथा पर्याप्त पुलिस एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अवैध मादक पदार्थों, पशु तस्करी, अवैध खनन, अवैध शस्त्र तस्करी और अन्य संगठित अपराधों के विरुद्ध अभियान चलाकर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। डीआईजी ने प्रभावी रात्रि गश्त सुनिश्चित करने तथा महिला सुरक्षा एवं साइबर अपराध नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया।

सपा—कांग्रेस का प्रदर्शनः जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन का जताया विरोध

संवाददाता—गोंडा। कर्नलगंज तहसील में आज मंगलवार देर शाम 4 बजे समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जौहर यूनिवर्सिटी के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के खिलाफ संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। यह ज्ञापन कांग्रेस प्रदेश सचिव त्रिलोकी नाथ तिवारी और सपा के करनैलगंज नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शमीम अहमद अच्छन के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया। इसमें विश्वविद्यालय को बचाने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है।

कांग्रेस व सपा नेताओं ने विश्वविद्यालय को शिक्षा का मंदिर बताते हुए कहा कि इसे ध्वस्त करने के बजाय शिक्षा और विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश सचिव त्रिलोकी नाथ तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विश्वविद्यालय को बचाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। नगर पालिका परिषद करनैलगंज के पूर्व अध्यक्ष शमीम अहमद अच्छन ने कहा कि सरकार द्वारा समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी को एक शिक्षा का मंदिर बताया, जहां से पढ़कर निकले छात्र देश की सेवा कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान अरविंद शुक्ला, फहीम अहमद पप्पू सहित दोनों दलों के अनेक नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से ध्वस्तीकरण कार्रवाई रोकने और मामले में न्यायोचित निर्णय लेने का आग्रह किया गया है। सपा नेता फहीम अहमद पप्पू ने कहा कि सरकार आज जिस तरीके से एक शिक्षा के मंदिर पर कार्रवाई करने जा रही है कहीं ना कहीं इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है दिल्ली में युवा मारे जा रहे हैं यहां पर शिक्षा का मंदिर गिराया जा रहा है।

पाकिस्तानी एजेंट के पिता बोले- दोषी है तो सजा मिले

शहरोज, आरोपी

संवाददाता—बलरामपुर। यूपी एटीएस (उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड) ने बलरामपुर से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नेटवर्क से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है। एटीएस का दावा है कि आरोपी आईएसआई के एक एजेंट और पाकिस्तानी गैंगस्टर के संपर्क में था। उनके कहने पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की तैयारी कर रहा था। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। उसके नेटवर्क की जांच जारी है। पाकिस्तानी एजेंट 5 दिन पहले मुंबई से बलरामपुर लौटा था। जिसका संपर्क राजस्थान में पाकिस्तान बार्डर के लोगों से था। खुफिया एजेंसियों के पास लोगों से बातचीत करने का साक्ष्य है। पाकिस्तानी एजेंट शहरोज के पिता इश्तियाक अली ने कहा— बेटा दोषी है तो सजा मिले। गैसड़ी कोतवाली क्षेत्र के जमथरा गांव निवासी पिता इश्तियाक अली जरवा थाने में होमगार्ड के पद पर तैनात हैं। एटीएस के अनुसार, अक्टूबर 2025 में आईएसआई एजेंट जसवीर चौधरी ने फेसबुक पर हिम्मत और जिगर वाले शूटर्स की आवश्यकता संबंधी एक पोस्ट साझा की थी। इस पोस्ट पर शहरोज ने प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद दोनों के बीच फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप और बाद में सिग्नल ऐप के माध्यम से बातचीत शुरू हुई। जांच एजेंसी का आरोप है कि जसवीर चौधरी के निर्देश पर शहरोज राजस्थान के श्रीगंगानगर से अवैध हथियार और गोला—बारूद लेने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए उसके बैंक खाते में पांच हजार रुपए भी भेजे गए थे। एटीएस का यह भी दावा है कि शहरोज पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क के संपर्क में भी था। एटीएस के मुताबिक, शहरोज मूल रूप से जमथरा गांव का रहने वाला है और पिछले कुछ समय से मुंबई में रहकर चिकन की दुकान चलाने के साथ वाहन चालक का काम कर रहा था। उसकी गतिविधियों पर कई दिनों से निगरानी रखी जा रही थी। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया।

मां अफरोज बानो ने बताया कि शहरोज 2000 से 2007 तक अपने पिता के साथ मुंबई में रहा। इसके बाद परिवार गांव लौट आया, जहां उसने बिशनपुर टंटनवा में सातवीं कक्षा तक पढ़ाई की। बाद में वह अकेले मुंबई चला गया और चिकन की दुकान पर काम करने लगा। कुछ समय उसने रजडेरवा चौराहे पर भी दुकान लगाई। करीब 6 महीने पहले वह फिर मुंबई गया था, जहां चिकन की दुकान और गाड़ी चलाता था। चार—पांच दिन पहले ही वह गांव लौटा था। परिवार का कहना है कि शहरोज को नशे की लत थी। वह शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करता था तथा अक्सर घर में विवाद करता था। इसी कारण परिवार के लोगों से उसकी नहीं बनती थी। पिता इश्तियाक अली ने बताया कि पिछले छह महीने से उनकी बेटे से कोई बातचीत नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, अगर मेरा बेटा दोषी है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए।

शहरोज का परिवार जमथरा गांव में रहता है। परिवार में पिता इश्तियाक अली, माता अफरोज बानो, तीन बहनें आरजू बानो, जुस्तजू बानो और उम्मे हबीबा तथा छोटा भाई कलीम दानिश शामिल हैं। शहरोज कक्षा आठ का पढ़ाई किया है। अभी शादी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को शहरोज गांव आया था और शुक्रवार को तुलसीपुर गया, जहां से यूपी एटीएस ने उसे हिरासत में ले लिया। इसके बाद सोमवार को एटीएस की टीम ने उसके घर की तलाशी भी ली। होमगार्ड इश्तियाक अली ने कहा कि पिछले छह महीने से उनकी बेटे से कोई बातचीत नहीं हुई थी। उनका कहना है कि यदि शहरोज दोषी है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। एटीएस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शहरोज के संपर्क में और कौन—कौन लोग थे, क्या कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है और मामले में अन्य लोगों की भी भूमिका है या नहीं। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

श्री रामलीला निवास में हर्षोल्लास से मनाया गया लीला बिहारी सरकार का पाटोत्सव

—भारतीय बस्ती संवाददाता अयोध्या। रामघाट स्थित श्री रामलीला निवास मंदिर में मंगलवार को भगवान श्री लीला बिहारी सरकार का पाटोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर को आकर्षक पुष्पों से सजाया गया। प्रातःकाल मां सरयू के पावन जल एवं पंचामृत से भगवान का अभिषेक कर नवीन वस्त्र धारण कराए गए। इसके बाद विधि—विधान से पूजा—अर्चना और महाआरती संपन्न हुई तथा ठाकुरजी को विविध व्यंजनों का महाभोग अर्पित किया गया।श्री रामलीला निवास के पीठाधीश्वर महंत चंद्रशेखर दास महाराज के सान्निध्य में आयोजित पाटोत्सव में बड़ी संख्या में संत—महंत एवं श्रद्धालु शामिल हुए। महंत चंद्रशेखर दास ने कहा कि रामानंदी संप्रदाय में सेवा को ही सर्वोपरि भक्ति माना गया है। गुरुदेव की कृपा से आश्रम में निरंतर संत सेवा, गौ सेवा और नारायण सेवा का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान का पाटोत्सव मंदिर का प्रमुख वार्षिक उत्सव है, जिसकी तैयारियां दो दिन पहले से शुरू हो जाती हैं और देशभर से संत—महंत इसमें सहभागी बनने के लिए अयोध्या पहुंचते हैं।उत्सव में तुलसीदास छावनी के महंत जनार्दन दास, महंत हरिभजन दास, महंत रामभजन दास, महंत रामभिलन दास, महंत रामकिशोर दास, महंत रामदास, विवेक दास, संत दास समेत सैकड़ों संत—महंत और श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर भगवान श्री लीला बिहारी सरकार का पूजन—अर्चन किया तथा प्रसाद ग्रहण कर धर्मलाभ प्राप्त किया।

350 से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाहः हिंदू—मुस्लिम रीति—रिवाज से हुई शादियां, डीएम—विधायकों ने दी बधाई

संवाददाता—गोंडा। जिले में मंगलवार दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था एक निजी मैरिज हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में 350 से अधिक जोड़ों ने विवाह किया। इन जोड़ों को जिला अधिकारी और विधायकों ने उपहार देकर बधाई दी।

कार्यक्रम के लिए गोंडा जिले के 16 विकास खंडों से कुल 526 लोगों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 350 से अधिक जोड़ों ने दस्तावेज सत्यापन के बाद विवाह संपन्न किया। इन जोड़ों में 50 से अधिक मुस्लिम और 300 से अधिक हिंदू जोड़े शामिल थे, जिनकी शादी उनके संबंधित रीति—रिवाजों के अनुसार कराई गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गोंडा की जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन,कटरा बाजार के भाजपा विधायक बावन सिंह,गोंडा सांसद के प्रधान प्रतिनिधि रमाशंकर मिश्रा और गोंडा भाजपा जिलाध्यक्ष इकबाल बहादुर तिवारी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को उपहार भेंट कर उनके नए जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं।इस अवसर पर भाजपा विधायक बावन सिंह ने बताया कि सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सहायता राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी है। उन्होंने कहा कि जोड़ों के खातों में धनराशि भेजी जा रही है और उन्हें शादी के समय उपहार भी दिए जा रहे हैं। विधायक ने जोर देकर कहा कि अब किसी भी गरीब परिवार की बेटी का हाथ पीला नहीं रहेगा, सरकार सभी की शादी कराएगी और घर बसाने में मदद करेगी। जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि यह जिला स्तरीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम था।उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर नवविवाहित जोड़ों का फूलों से स्वागत किया। डीएम ने यह भी सुनिश्चित किया कि जोड़ों को उपहार दिए गए हैं और उनके खातों में पैसे भेजे गए हैं। उन्होंने पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि यदि कहीं भी भ्रष्टाचार या लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दो अलग—अलग चरण में यहां पर शादियां कराई गई है सभी नवविवाहित जोड़ों को सामानों की भी वितरण बहुत ही गंभीरता पूर्वक किया जा रहा है जहां लोग ई रिक्शा बुलाकर के अपने—अपने घर जा रहे हैं।

थप्पड़ के बदले कत्ल, दोस्तों की खतरनाक साजिश शराब पिलाई फिर डंडे से पीटकर मार डाला

संवाददाता–गोरखपुर। हरपुर बुढ़हट थाना क्षेत्र के प्रेमसागर यादव (उम्र 30 वर्ष) हत्याकांड का पुलिस ने मंगलवार को पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि तीन माह पहले शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद और थप्पड़ मारने की घटना का बदला लेने के लिए उसके दो दोस्तों ने ही हत्या की साजिश रची थी। योजना के तहत पहले प्रेमसागर को शराब पिलाई गई, फिर सुनसान स्थान पर ले जाकर रॉड और डंडे से हमला कर मरा समझकर सड़क किनारे छोड़ दिया था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि 19 जुलाई की सुबह बैजलपुर ग्राम पंचायत भवन के पास सड़क किनारे प्रेमसागर यादव अचेत अवस्था में मिला था। राहगीरों की सूचना पर परिजन उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता ज्ञानेंद्र यादव की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मोबाइल कॉल डिटेल का सहारा लिया। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने संतकबीरनगर के खलीलाबाद थाना क्षेत्र के रावतपार निवासी अखिलेश यादव (उम्र 20 साल), अजीत कुमार यादव उर्फ सिंटू (उम्र 40 साल) और मामतपुर कठर निवासी सुधीर यादव (उम्र 21 साल) को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और विवेचना में तीनों की साजिश का खुलासा हुआ।

पुलिस के अनुसार करीब तीन माह पहले शराब पार्टी के दौरान प्रेमसागर यादव और उसके दोस्त अखिलेश यादव व अजीत कुमार यादव उर्फ सिंटू के बीच कहासुनी हो गई थी। विवाद के दौरान प्रेमसागर ने सिंटू को थप्पड़ मार दिया था। इसी घटना के बाद दोनों आरोपियों ने मन में दुश्मनी पाल ली और बदला लेने का मौका तलाशने लगे। पुलिस के मुताबिक दोनों लगातार फोन पर बातचीत कर प्रेमसागर की हत्या की योजना बना रहे थे। 18 जुलाई की शाम अखिलेश यादव योजना के तहत प्रेमसागर को अपने साथ गिठनी चौराहे पर ले गया और उसे अत्यधिक शराब पिलाई। जब वह पूरी तरह नशे में हो गया तो अखिलेश ने अजीत उर्फ सिंटू को फोन कर बुलाया। सिंटू अपने साथी सुधीर के साथ सफेद रंग की महिंद्रा कार लेकर मौके पर पहुंचा। तीनों ने नशे में धुत प्रेमसागर को कार में बैठाया और बैजलपुर–सीउवा पार मार्ग के पास सुनसान स्थान पर ले गए। वहां तीनों ने रॉड और डंडे से उसकी बेरहमी से पिटाई की। हमले के दौरान प्रेमसागर के सिर पर रॉड से गंभीर चोट लगी, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ा। आरोपियों ने उसे मृत समझकर सड़क किनारे छोड़ दिया और कार से फरार हो गए। गंभीर हालत में मिले प्रेमसागर को परिजनों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, लेकिन करीब 24 घंटे तक चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई।

राम मंदिर चढ़ावा चोरीः एसआईटी की दोबारा जांच से बढ़ेंगी कइयों की मुश्किलें

संवाददाता–अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय के नए आदेश ने कइयों को बेचैन कर दिया है। न्यायालय के आदेश पर अगर इस मामले की दोबारा जांच हुई, तो न केवल यह अधिक प्रभावी होगी, बल्कि अब तक की जांच व पूछताछ से बच गए लोगों पर भी कार्रवाई होने के आसार बढ़ जाएंगे। कोर्ट का यह आदेश ट्रस्ट के उन पदाधिकारियों को भी मुश्किलों में डालेगा, जिन पर तमाम सवाल उठते रहने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माना जा रहा कि एसआईटी की दोबारा होने वाली जांच में आरोपितों की संख्या भी बढ़ सकती है। अब तक उन बैंक अधिकारियों या कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिन पर दानराशि की गणना का समस्त दायित्व था, फिर भी इनकी निगरानी में हर कदम पर लापरवाही बरती गई।

राज्य सरकार के आदेश पर चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने से पहले ही, 20 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए अब तक की जांच व कार्रवाई से असंतुष्टि जताकर नए सिरे से जांच कराने और अनुभवी आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने का आदेश दे दिया है। न्यायालय का यह आदेश सार्वजनिक होते ही उन रामभक्तों के चेहरों पर प्रसन्नता छा गई, जिन्हें राम मंदिर में चढ़ावा चोरी उजागर होते ही गहरा आघात लगा था। वहीं, ऐसे लोग सशंकित भी हो उठे हैं, जो एसआईटी व पुलिस की जांच के बाद भी कार्रवाई के दायरे से बाहर हैं और ऐसे लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज नहीं हुई।

सोमवार को अदालत के आदेश को लेकर मंदिर परिसर से लेकर रामनगरी तक, चहुंओर इसकी व्यापक चर्चा रही। अधिकांश लोगों ने यही संभावना जताई कि अब ऐसे लोग भी सामने लाए जा सकते हैं, जिनसे लंबी पूछताछ हुई, जो स्वयं सशंकित भी रहे, लेकिन एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद 25 जून 2026 को दर्ज हुई प्राथमिकी से बाहर रह गए। इनमें आउटसोर्स कंपनी के गणना कर्मियों के साथ निगरानी करने वाले बैंक व ट्रस्ट के कर्मी भी शामिल हैं। एसआईटी ने भले ही प्रारंभिक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि बैंक अधिकारियों व ट्रस्ट पदाधिकारियों के बीच वित्तीय पारदर्शिता को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तो तय की गई थी, इन पर बाकायदा हस्ताक्षर भी किए गए थे, परंतु इन किसी नियमों का सही से पालन नहीं कराया गया। इनमें आउटसोर्स कंपनी के गणना कर्मियों के साथ निगरानी करने वाले बैंक व ट्रस्ट के कर्मी भी शामिल हैं। एसआईटी ने भले प्रारंभिक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि बैंक अधिकारियों व ट्रस्ट पदाधिकारियों के बीच वित्तीय पारदर्शिता को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तो तय की गई थी, इन पर बाकायदा हस्ताक्षर भी किए गए, परंतु किसी नियमों का पालन नहीं कराया गया।

गणना करके निकलते समय कर्मियों की तलाशी भी नहीं कराई जा रही थी, जिसका लाभ उठाते हुए दान चोरी को अंजाम दिया गया।

चाची के दाहसंस्कार में आया युवक आमी नदी में डूबा

संवाददाता–गोरखपुर। खजनी थाना क्षेत्र के इटैली गांव में चाची के दशगात्र संस्कार में शामिल होने आया एक युवक मंगलवार को आमी नदी में स्नान के दौरान डूब गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और बाद में एसडीआरएफ की टीम की मदद से घंटों तलाश कराई, लेकिन शाम तक युवक का पता नहीं चल सका। इटैली गांव निवासी स्व. जोगिंदर प्रसाद के पुत्र रणविजय (37) अपनी पट्टीदारी की चाची के दसवें संस्कार में शामिल होने आए थे। परंपरा के अनुसार बाल मुंडवाने के बाद वह आमी नदी में स्नान करने उतरे। स्नान के दौरान वह गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव के कारण वह लापता हो गए। सूचना मिलते ही खजनी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से खोजबीन शुरू कराई। सफलता नहीं मिलने पर जिले से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। टीम ने स्टीमर के जरिए घंटों सर्च अभियान चलाया, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिला। इस हादसे से परिवार में कोहराम मच गया। जिस घर में पहले से एक मौत का मातम था, वहां इस घटना ने दुख और बढ़ा दिया। एसएचओ जयंत सिंह ने बताया कि स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की मदद से युवक की तलाश जारी रहा।

रक्तदान शिविर में 11 ने किया रक्तदान

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सावन कृपाल रूहानी मिशन द्वारा कृपाल आश्रम मंगलबाजार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 11 लोगों ने रक्तदान किया।

सावन कृपाल रूहानी मिशन के अध्यक्ष तीरथ दास ने बताया कि मिशन द्वारा मानवता की सेवा के लिये रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। सचिव चेतन आनन्द ने कहा कि रक्तदान के द्वारा हम संकट के समय लोगों की जान बचाकर पुण्य के भागी बनते हैं। यह क्रम मानव सेवा के उद्देश्य से निरन्तर जारी है। रक्तदान शिविर में निर्मित, विकास गुप्ता, आदेश बरनवाल, मनीष पटेल, तुसार आनन्द, दिलीप गुप्ता, धर्मेन्द्र, अनिल गुप्ता, पुनीत नानवानी, नवीन गुप्ता, धर्मेन्द्र कुमार आदि ने मानव सेवा के उद्देश्य से अपना रक्त दिया।

रक्तदान करने वालों को उपहार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। शिविर को सम्पन्न कराने में बस्ती चेरीटेबल ब्लड बैंक के शिवम मिश्र, संदीप चौधरी, जितेन्द्र आदि ने योगदान दिया।

अनुचर ने लगाया उत्पीड़न का आरोप 22 जुलाई से आन्दोलन की चेतावनी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के मंडल महासचिव एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर प्रेम नंदवंशी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर भारत सिंह कृषि विद्यालय, भारत नगर, तेंनुआ, हर्रैया में अनुचर पद पर कार्यरत मनोज कुमार वर्मा के कथित उत्पीड़न, लंबित वेतन एवं ग्रेच्युटी के भुगतान, सेवा बहाली तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समय रहते निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो 22 जुलाई से शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक विरोध–प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। ज्ञापन के अनुसार मनोज कुमार वर्मा ने आरोप लगाया है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा कई वर्षों से उनका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न किया जा रहा है। उनका वेतन लंबे समय से लंबित है तथा लगभग दस वर्षों से ग्रेच्युटी का भुगतान भी नहीं किया गया। इसके अलावा सेवा बहाली के मामले में भी उन्हें न्याय नहीं मिल सका है।

ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि वेतन और ग्रेच्युटी की मांग करने पर उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई तथा विद्यालय प्रबंधन द्वारा कथित रूप से सेवा बहाली के बदले अवैध धनराशि की मांग की गई। साथ ही संबंधित अधिकारियों पर शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा ने जिलाधिकारी से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने, मनोज कुमार वर्मा का लंबित वेतन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान सुनिश्चित कराने तथा उनकी सेवा बहाल करने की मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि यदि 22 जुलाई 2026 तक न्यायोचित कार्रवाई नहीं होती है तो शांतिपूर्ण, अहिंसात्मक एवं संवैधानिक दायरे में अनिश्चितकालीन विरोध–प्रदर्शन किया जाएगा।

दिल्ली लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पर जुलूस निकाल राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा

संवाददाता–संतकबीरनगर। जनपद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने दिल्ली पुलिस द्वारा युवाओं पर किए गए कथित लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के प्रयोग के विरोध में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन खलीलाबाद स्थित कलेक्ट्रेट पर मंगलवार को 12 बजे जुलूस निकालकर किया गया।

प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और घटना की निष्पक्ष जांच तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।

जनपद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार चौधरी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई से बड़ी संख्या में युवा घायल हुए हैं। अधिवक्ताओं ने मांग की कि युवाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी अपील की।

इस अवसर पर महामंत्री राम अवतार यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार पांडेय, उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार प्रजापति, अवधेश पांडेय, कोषाध्यक्ष मधुसूदन दुबे, इमरान खान, दिलीप चौधरी, महेंद्र कुमार, लालचंद, शैलेश कुमार, रामप्रसाद श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

भाकियू ने बाइक जुलूस निकाल किया प्रदर्शन, अपर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

संवाददाता–संतकबीरनगर। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने मंगलवार को किसानों की 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। संगठन ने खलीलाबाद स्थित गन्ना समिति तितौवा से कलेक्ट्रेट तक मोटरसाइकिल जुलूस निकाला। इसके बाद जिलाध्यक्ष प्रेमनाथ उर्फ गुड्डू चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों के शीघ्र समाधान की मांग की गई। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि देश का किसान लगातार बढ़ती खेती की लागत, फसलों का उचित मूल्य न मिलने, प्राकृतिक आपदाओं और महंगे डीजल, बिजली, बीज व कृषि यंत्रों की बढ़ती कीमतों से परेशान है। भाकियू ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो इसका सीधा असर देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। संगठन ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी लागू करने की मांग की। भाकियू ने किसानों और कृषि मजदूरों का संपूर्ण ऋण माफ करने, ब्याजमुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने, कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को 300 यूनिट निशुल्क बिजली देने की मांग उठाई। संगठन ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था और बिजली के निजीकरण को वापस लेने की भी मांग की।

जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में मलौना गांव में रेलवे परियोजना से प्रभावित भूमि का मुआवजा दिलाने, जनपद की जर्जर सड़कों की मरम्मत, नहरों की सफाई, खाद–बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, अघोषित बिजली कटौती पर रोक लगाने, छुट्टा पशुओं की समस्या का समाधान करने और दवाओं की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने सहित अन्य स्थानीय समस्याओं के निस्तारण की मांग की गई। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो किसान आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस प्रदर्शन के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र, किसान बस्ती के महासचिव ब्रह्मदीन चौधरी, जिला महासचिव रामाशंकर यादव, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामदरस यादव, जिला प्रवक्ता मन्नू प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष विजयनाथ पाठक, जिला सचिव इंद्रेश, ध्रुव चंद्र, सनी, करम हुसैन, हृदय राम यादव, रामसागर चौधरी, कुतुबुद्दीन, रामसुरेश चौधरी और दयाशंकर उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

कटसहरा में एक ही रात दो स्कूलों में चोरी

संवाददाता–गोरखपुर। हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कटसहरा स्थित प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सोमवार रात चोरों ने धावा बोल दिया। दोनों विद्यालयों को निशाना बनाकर चोर मिड–डे मील का राशन और रसोई में इस्तेमाल होने वाला सामान चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी मंगलवार सुबह विद्यालय खुलने पर हुई। दोनों प्रधानाध्यापकों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक कमलेश कुमार ने बताया कि चोर कमरे की कुंडी तोड़कर अंदर घुसे और दो एल्यूमीनियम के फाटक, सात लीटर का कुकर, एक भगौना, 50 किलो चावल, 10 किलो गेहूं समेत अन्य सामान उठा ले गए।

वहीं पूर्व माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका संध्या भारती ने बताया कि चोर खिड़की की ग्रिल काटकर विद्यालय में दाखिल हुए। यहां से 50 किलो चावल, 25 किलो गेहूं, सात लीटर का कुकर, दो भगौने, दो बड़े पलटे, एक करछूल, एक स्टील की बाल्टी सहित अन्य रसोई का सामान चोरी कर लिया। थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार पाठक ने बताया कि दोनों विद्यालयों से चोरी की तहरीर मिल गई है। घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जल्द ही चोरी का खुलासा कर आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।

68 हजार बकायेदारों को बड़ी राहत, माफ होगा ब्याज

संवाददाता–गोरखपुर। गोरखपुर के बकायेदारों के लिए खुशखबरी है। नगर निगम में गृहकर, जलकर और सीवरकर का 257 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें 186 करोड़ रुपये मूल कर और 71 करोड़ रुपये ब्याज शामिल हैं। प्रदेश सरकार की ओटीएस लागू होने से महानगर 68 हजार ब्याज माफी का लाभ मिलेगा।

गोरखपुर नगर निगम में गृहकर, जलकर और सीवर टैक्स का 257 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें 186 करोड़ रुपये मूल कर और 71 करोड़ रुपये ब्याज शामिल हैं। प्रदेश सरकार की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू होने से महानगर 68 हजार बकायेदारों को ब्याज माफी का लाभ मिलेगा, वहीं नगर निगम बड़े पैमाने पर बकाया वसूली अभियान चलाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में संपत्ति कर की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने का फैसला किया है। गोरखपुर नगर निगम में इस योजना का सीधा लाभ करीब 68 हजार बकायेदारों को मिलेगा, जिन पर कुल 257 करोड़ रुपये का गृहकर, जलकर और सीवरकर बकाया है। इसमें 186 करोड़ रुपये मूल कर तथा 71 करोड़ रुपये ब्याज और सरचार्ज का है। 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक संचालित होने वाली इस योजना के तहत मूल बकाया जमा करने पर ब्याज और सरचार्ज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। करदाता चाहें तो बकाया राशि अधिकतम तीन किस्तों में भी जमा कर सकेंगे। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किए जाएंगे तथा नगर निगम में इसके लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित की जाएगी। नगर निगम अब ओटीएस योजना के जरिए अधिक से अधिक बकायेदारों से कर जमा कराने की रणनीति पर काम करेगा।

घर में काम करने आए कारीगर ने जेवर चुराए, 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। खेसरहा थाना पुलिस ने घर से आभूषण चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी के सोने–चांदी के जेवर और बिक्री से प्राप्त 26,200 रुपये नकद बरामद किए हैं। आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया है। यह कार्रवाई थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्र के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान बांसी थाना क्षेत्र के मलौली निवासी परमात्मा शर्मा पुत्र स्व. दलसिंगार शर्मा के रूप में हुई है। उसके खिलाफ खेसरहा थाने में मुकदमा संख्या 98/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305(ए) के तहत मामला दर्ज था। बरामदगी के बाद इसमें धारा 317(2) बीएनएस भी जोड़ी गई है। पुलिस के अनुसार, एचनी गांव निवासी शैलकुमारी पत्नी गंगासागर ने 20 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई को उनके घर में एल्यूमीनियम के दरवाजे और खिड़की लगाने का काम चल रहा था। इसी दौरान कारीगर परमात्मा शर्मा ने मौका पाकर घर के बक्से में रखे सोने–चांदी के जेवर चुरा लिए। चोरी का पता 18 जुलाई को चला, जिसके बाद काफी खोजबीन के बाद भी जेवर नहीं मिलने पर पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मंगलवार को बांसी–धानी मार्ग पर बंजरहा जाने वाले रास्ते से आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक मंगलसूत्र, एक माथा टीका, एक कान का झाला, एक जोड़ी चांदी की पाजेब और गहनों की बिक्री से मिले 26,200 रुपये नकद बरामद हुए। बरामद आभूषणों की अनुमानित कीमत लगभग 1.80 लाख रुपये बताई गई है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम में सकारपार चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक कुंज बिहारी तिवारी, कांस्टेबल अवनीश राय, अखिलेश कुमार और कमलेश सिंह शामिल थे।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं मौली चौधरी पुत्री रामधनी चौधरी निवासी पाण्डेय पोखरा महरीखांवा पोस्ट– गांधीनगर जनपद बस्ती (उ.प्र.) की निवासिनी हूं। मैंने अपना नाम मौली चौधरी से बदलकर मान्या चौधरी कर लिया है। मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाय।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील

निगरानी सं0– 703/2024

वाद सं0–1302/24

अदालत– श्रीमान उप संचालक चकबन्दी महोदय बस्ती जिला–बस्ती

इन्द्रपति

बनाम

श्याम नरायन आदि

1. श्याम नरायन 2. विजय नरायन पुत्रगण सरस्वती प्रसाद 3. मुन्नी देवी विधवा सरस्वती प्रसाद निवासी ग्राम अठदमा तप्पा हवेली परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 05–08–2026

अपील बनराजी आदेश के अदालत ब0अ0च0 मुकाम बस्ती

मयरिखा 20 महीना 08 सन् 2024 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी इन्द्रपति ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 05 महीना 08 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी। आज बतारीख 20 माह 07 सन 2026 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील

अपील सं0– 754/2026

अदालत– श्रीमान बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी महोदय बस्ती जिला–बस्ती

रामचेत आदि

बनाम

रामफेर आदि

1. द्वारिका 2. राजू 3. संजय 4. सुनील पुत्रगण राजकुमार साकिनान मौजा जमालपुर तप्पा कुदरहा परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 12–08–2026

अपील बनराजी के अदालत मुकाम बस्ती

मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 12 महीना 08 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी। आज बतारीख 21 माह 07 सन 2026 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा

(आर्डर 22, कायदा 4)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला–बस्ती

मूलवाद सं0–532/2018

तामेश्वर प्रसाद

बनाम

हरिवंश सिंह आदि

2/1 धामासिंह उम्र लगभग 66 साल विधवा लक्ष्मी सिंह उर्फ लक्ष्मी नारायण सिंह 2/2 रंजीत सिंह उम्र लगभग 38 साल 2/3 अजय सिंह उम्र लगभग 34 साल पुत्रगण स्व0 लक्ष्मी सिंह उर्फ लक्ष्मी नारायण सिंह 3/1 बविता सिंह उम्र लगभग 45 साल विधवा महेन्द्र सिंह 3/2 देवाश सिंह उम्र लगभग 25 साल 3/3 शिवेन्द्र प्रताप सिंह उम्र लगभग 23 साल पुत्रगण स्व0 महेन्द्र सिंह निवासीगण मौजा मरवटिया तप्पा दुबखरा परगना नगर पूरब तहसील बस्ती सदर जिला बस्ती

तारीख पेशी 17–08–2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 17 माह 08 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा

(आर्डर 22, कायदा 4)

न्यायालय–श्रीमान पंचम अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती

वाद सं0–35/2018

राममूरत

बनाम

श्रीमती कलावती आदि

4/1 अनिरूद्ध 4/2 अभिमन्यु पुत्रगण कमला प्रसाद निवासीगण ग्राम जगदीशपुर तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती

तारीख पेशी 17–08–2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 17 माह 08 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरा नाम सानिया SANIYA पुत्री इन्तजारूल हक INTEZARUL HAQUE बेगम खैर कालोनी गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) की निवासिनी हूं। मेरा आईसीएसई हाईस्कूल बोर्ड वर्ष **2026** अनुक्रमांक **1267959/136** के अंक पत्र में पिता का नाम इन्तजारूल हक INTEZARUL HAQUE के स्थान पर INTEZARUL HAQ SIDDIQUI इन्तजारूल हक सिद्दीकी हो गया है जो गलत है। उसे सुधारकर इन्तजारूल हक INTEZARUL HAQUE कराया जाय।

दैनिक भारतीय बस्ती

संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**

संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**

अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद

लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।

गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।

मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल **bhartiyabasti@gmail.com**
dainikbhartiyabasti@gmail.com